डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 फरवरी, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 फरवरी, 2022

| वर्ष 65 | अंक 17 | भोपाल | 1 फरवरी, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र : राज्यपाल श्री पटेल

जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाएँ : राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल : राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है। उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया है कि सब मिलकर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने देश की स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

राज्यपाल श्री पटेल लाल परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित किया

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि देश के जन-जन के हृदय में बसने वाले हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था। दो वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टॉस्क फोर्स गठित की थी। "दवाई भी-कड़ाई भी" का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व एवं प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। अब तक पूरे देश में टीके के 162 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। मरीज़ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को देशभर में सराहा गया है। टीकाकरण में भी प्रदेश अग्रणी बना। कोविड की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिये भी सरकार ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएँ की हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मुख्यमंत्री श्री चौहान का गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम संदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नेहरू स्टेडियम इंदौर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, ली परेड की सलामी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की दी बधाई

इंदौर : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देते हुये अपने संदेश में कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। देश में 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वाँ जन्म-दिन मनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के जन्म-दिन को पराक्रम दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया। गणतंत्र दिवस के पर्व पर मैं नेता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश को आजादी कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रखकर भेंट नहीं की थी। एक तरफ पूज्य बापू जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अपने रक्त की अंतिम बूँद से भारत माता की पवित्र माटी को रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कहते हुए कभी-कभी तकलीफ होती है कि स्वतंत्रता के बाद हमें आजादी का इतिहास तक गलत पढ़ाया गया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

हर किसान को फसल क्षति का मुआवजा दिलाया जाएगा-कृषि मंत्री श्री पटेल

हरदा। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि गत दिनों ओला पाला से प्रभावित फसलों का मुआवजा प्रत्येक किसान को उसकी पात्रता अनुसार दिलाया जाएगा। किसी भी अपात्र व्यक्ति को मुआवजा न मिले, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने सर्किट हाउस हरदा में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत फसल क्षति अनुसार मुआवजा दिलाने के लिये राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी सर्वे कर चुके है तथा सर्वे में फसल क्षति के आधार पर किसानों के खातों में राहत की राशि अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति केवल किसान की क्षति नहीं है बल्कि राष्ट्र की क्षति है इसलिये किसानों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। उन्होने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत राहत राशि के अलावा फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को बीमा कम्पनी से फसल बीमा की राशि यथा शीघ्र दिलाने के प्रयास किये जा रहे है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पहले वन ग्रामों के किसानों की फसल का बीमा नहीं होता था लेकिन प्रदेश सरकार ने अब वन ग्राम के किसानों की फसल का भी बीमा कराया है।

2 तहसीलों के 51 ग्रामों में हुई प्राकृतिक आपदा से क्षति

कृषि मंत्री श्री पटेल ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि फसल सर्वे के बाद प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की 2 तहसीलों के 51 ग्रामों की फसल गत दिनों ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें रहटगांव तहसील के 31 गांव व हरदा तहसील के 20 गांव शामिल है। प्रभावित फसल में गेहूँ व चना की फसल शामिल है। उन्होने बताया कि रहटगांव तहसील के कुल 3597 किसानों के खेतों में 6506.07 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है जबकि हरदा तहसील के कुल 3785 किसानों के खेतों में 7616 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है। इस तरह कुल 51 ग्रामों के 7382 किसानों के खेतों में 14124.1 हेक्टेयर फसल ओला वृष्टि से प्रभावित हुई है।

जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को पोषण भत्ते की राशि अंतरित करते हुए।

भोपाल। विशेष पिछडी सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की बहनों की जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है। रोटी, कपडा, मकान, पढाई-लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की महिला को आहार अनुदान की राशि के वर्चुअल अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय कार्य विभाग की आहार अनुदान योजना में 2 लाख 30 हजार 969 पात्र महिला हितग्राहियों को जनवरी 2022 की 23 करोड़ 9 लाख 69 हजार रूपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। राज्य शासन द्वारा इन तीन जनजाति वर्ग की महिलाओं को आहार अनुदान योजना में प्रतिमाह एक- एक हजार रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में 14 जिलों की सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की बहनें वर्चुअली सम्मिलित हुई।

संबोधन के दौरान मुख्य0मंत्री ने शहडोल जिले की श्रीमती रमनी बैगा एवं श्रीमती संगीता भारती और दतिया जिले की श्रीमती प्रभा सहरिया एवं श्रीमती गीता सहरिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सहरिया बैगा और भारिया जनजाति के विकास और कल्याण के लिए राज्यी सरकार कोई कमी नहीं छोड रही है। उन्होने कहा कि स्व- सहायता समूहों के माध्यनम से महिलाओं को रोजगार से भी जोडा जा रहा है।

देश में दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ा

नई दिल्ली। देश में रबी फसलों की बोनी 679 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर से अधिक है। क्योंकि गत वर्ष 671 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इसमें गेहूं की बोनी अब तक 340.82 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 345.14 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। वहीं दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ा है। सरसों के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है तथा मोटे अनाजों के रकबे में कुछ कमी बनी हुई है।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक अब तक देश में 679.34 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं। जबकि गत वर्ष इस अवधि में 671.98 लाख हेक्टेयर में फसलें ली गई थी। ज्ञातव्य है कि रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 625.14 लाख हेक्टेयर है। देश में गेहूं के रकबे में गत वर्ष की तुलना में लगभग 4.31 लाख लेक्टेयर की कमी है। अब तक गेहूं 340.82 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। जबकि गत वर्ष अब तक 345.14 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोनी हो गई थी। वहीं सामान्य क्षेत्र 303.06 लाख हेक्टेयर है।

सहकारिता मंत्री ने अटेर क्षेत्र में 3 करोड़ 74 लाख से अधिक लागत के कई निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण,भूमिपूजन

भिण्ड। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन विभाग मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया अटेर क्षेत्र के भ्रमण पर रहे जहाँ उनके द्वारा ग्राम पंचायत रिदौली, परा, कदौरा एवं खरिका में 3 करोड़ 74 लाख से अधिक लागत के कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री जेके जैन, एसडीएम अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन विभाग मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया ग्राम पंचायत रिदौली में 36 लाख 85 हजार की लागत के दो निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। जिसमें 24 लाख की लागत से निर्मित होने वाली एक सुदूर सम्पर्क सड़क का भूमिपूजन एवं 12 लाख 85 हजार की लागत से निर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने परा में 2 करोड़ 93 लाख 92 हजार की लागत के 5 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें 2 करोड़ 73 लाख की लागत की परा-बोरेश्वर मार्ग लोकार्पण के साथ 20 लाख से अधिक के चार अन्य निर्माण जिसमें बाउंड्री वॉल निर्माण, नाला निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण एवं सीसी रोड निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कदौरा में 23 लाख 23 हजार की लागत के तीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें 12 लाख की लागत से निर्मित सुदूर सम्पर्क सड़क, 7 लाख 80 हजार की लागत से निर्मित आंगनवाड़ी भवन एवं 3 लाख 43 हजार की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ उनके द्वारा ग्राम पंचायत निवारी (खरिका) में 20 लाख 49 हजार की लागत के 3 निर्माण कार्यों लोकार्पण भी किया गया। जिसमें 8 लाख की लागत से चबूतरा निर्माण, 8 लाख की लागत से नाली निर्माण एवं 4 लाख 49 हजार की लागत निर्मित बाउंड्रीवॉल का लोकार्पण शामिल रहा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया ने लोकार्पण/भूमिपूजन के अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। सभी इलाकों का सर्वांगीण विकास हो, लोगों को आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ परिवेश, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें आदि सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चम्बल एक्सप्रेस-वे को अटल प्रगति पथ का जो नया नाम दिया गया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि अटल प्रगति पथ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक्सप्रेस-वे से मिलेगा। राज्य शासन इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेगा जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसानों को दी जाएगी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी

पीएम खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सब्सिडी आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है | जिसके तहत देश के युवा किसानों को अपना बिज़नस शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है | केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे "एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम" के तहत किसान ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित कर अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं | सरकार किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ भी मुहैया करा रही हैं | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरुद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी-छोटी फ़ूड प्रोसेसिंग इकाई खोल लें, तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इनक्यूबेशन

सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे।

किसानों को दी जाएगी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के संबंध में जानकारी देने और इनकी प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में किसान को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान का 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार बड़ी यूनिट लगाने पर ढाई करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख इकाइयाँ काम कर रही हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में असंगठित खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। इनमें से लगभग 66 प्रतिशत यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 80 प्रतिशत उद्यम परिवार आधारित हैं। यह उद्यम, ग्रामीण पारिवारिक आजीविका को बढ़ाने और ग्रामीणों के शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने में सहायक हैं। अत: ग्राम स्तर पर खाद्य प्र-संस्करण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी तथा सामग्री की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण और वेल्यू एडिशन पर सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है।

इन जिलों में होगी तीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना सीहोर, मुरैना और ग्वालियर में तीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 9 करोड़ 87 लाख 85 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। सीहोर में अमरूद, फलों तथा सब्जियों के प्र-संस्करण के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। सेंटर में खाद्य प्र-संस्करण प्रयोगशाला सहित जूस, पल्प, जैम, जैली, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन लाइन एवं प्याज प्र-संस्करण लाइन की स्थापना होगी। मुरैना में सरसों एवं अन्य तिलहनों, ज्वार, बाजरा, रागी और बेकरी उत्पादों के प्र-संस्करण के लिए कॉमन इन्क्यूबेशन फेसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर में आलू तथा आलू प्र-संस्करण लाइन एवं मिलेट आधारित कुकीज लाइन की स्थापना की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आत्म-निर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की शुरूआत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों का विकास तथा "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उद्यानिकी फसलें जैसे आम, आलू, टमाटर आदि जल्द खराब होते हैं। इनके रख-रखाव, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए योजना में विशेष व्यवस्था है।

बालाघाट जिला सहकारी बैंक ने पशुपालकों को 95 लाख का ऋण स्वीकृत किया

बालाघाट। केसीसीधारी कृषको को पशुपालन हेतु कार्यशील पूंजी साख सीमा स्वीकृति योजना में बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पात्र पशुपालकों को कार्यशील पूंजी मंजूर की गई है। डॉ गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर व बैंक प्रशासक के निर्देशन में राजीव सोनी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा शाखा बैहर, वारासिवनी, खैरलांजी, भानेगांव, खमरिया, मुख्य शाखा बालाघाट की समितियों के लगभग 410 पशुपालकों को लगभग राशि 95 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है।

इसी तारतम्य में राजीव सोनी प्रभारी सीईओ ने बताया कि 15 जनवरी को डॉ पी.के. अतुलकर पशु चिकित्सा सेवाए बालाघाट द्वारा बैंक मुख्यालय पहुंचकर श्री मिश्रा कलेक्टर बालाघाट के निर्देशानुसार केसीसीधारी कृषको को पशुपालन हेतु कार्यशील पूंजी साख सीमा स्वीकृति के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान राजेश नगपुरे फील्ड अधिकारी बैंक मुख्यालय, गणेश बागरे सहायक पशु छेत्र अधिकारी उपस्थित रहे।

गरीबों का राशन किसी को खाने नही देंगें- मुख्यमंत्री

शहडोल- प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में राशन दुकानों के माध्यम से गरीब और कमजोर तबके के लोगों को राशन वितरण की व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर और पारदर्शी बनाने के उददेश्य से राशन दुकानों की रेंडम जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारी राशन दुकानों की रेंडम ली जांच करें और राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रमण के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन नही मिलने की शिकायतें मिली थी, शिकायतों की जांच कराई गई तथा अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में गरीबों का राशन किसी को खाने नही देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जो राशन वितरण किया जाता है इस राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रमण के समय वह स्वयं राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज कमिश्नर्स, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में नागरिकों को शुद्व और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलावटी वस्तुएं बेचकर लोगों की जिदंगी से खेलने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्व और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर कान्फ्रेंस में कानून व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टॉपू बना रहें इसके सतत प्रयास होने चाहिए। प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं एवं गुंडों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडो, माफियाओं और अपराधियों को नेस्तनाबूत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित अपराधों में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार उदासीनता नही होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में सक्रिय चिटफंड कम्पनियों एवं एनजीओ की गतिविधियों पर भी निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देष दिए कि समाज में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशामुक्ति अभियान भी चलाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं विरूद्व अपराध रोके। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन मुस्कान की भी समीक्षा। कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़के ठीक होना चाहिए, बरसात से पहले सभी सड़कों की मरम्मत हो जाना चाहिए।

बाँस की फसल अन्य फसलों से सुरक्षित और लाभदायक : प्रमुख सचिव वन श्री वर्णवाल

भोपाल : बाँस की फसल अन्य फसलों की तुलना में सुरक्षित और अधिक लाभदायक है। बाँस की फसल की खासयित यह भी है कि यह किसी भी मौसम में खराब नही होती। प्रमुख सचिव, वन श्री अशोक वर्णवाल ने यह बात हरदा में बाँस वृक्षरोपण के लिए कृषकों की एक दिवसीय कार्यशाला में कही।

प्रमुख सचिव श्री वर्णवाल ने बताया कि बाँस की फसल इस दृष्टि से भी बेहत्तर है कि इसे एक बार लगाने के बाद हर साल इसका उत्पादन प्राप्त होता है। बाँस की फसल में खर्चा कम होने के साथ मानव श्रम भी बहुत कम लगता है। एक हेक्टेयर में 625 पौधे लगाये जा सकते है। किसान शासकीय नर्सरी से बाँस के पौधे खरीद सकते है। उन्होंने कहा कि बाँस की फसल पर्यावरण के लिए लाभकारी, हरियाली बढ़ाने के साथ तापमान संतुलित करने में सहायक है।

राज्य बाँस मिशन के सी.ई.ओ. डॉ. यू.के. सुबुद्धि ने बताया कि राज्य बाँस मिशन योजना में किसानों द्वारा निजी भूमि पर बाँस रोपण किया जाता है। रोपित बाँस के पौधों के लिए 3 वर्ष में 120 रूपये प्रति पौधे के मान से किसान को अनुदान दिया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और किसान मौजूद थे।

जिले की सहकारी क्षेत्र व प्रथम सामान्य सुविधा केन्द्र का शुभारंभ

झाबुआ। जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रंभापुर कार्यालय में आत्मनिर्भर योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र शुभारंभ जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक आर.एस. वसुनिया के कर कमलो द्वारा सरस्वती पूजन एवं शुभारंभ किया गया। सामान्य सुविधा के एमपी ऑनलाइन से पंजीकृत है। शासन की योजना अनुसार एमपी ऑनलाइन कियोस्क की सभी सुविधाएं सहकारी समिति के इस केन्द्र से कृषकों, उपभोक्ताओं, ग्रामीण व आम नागरिक को प्राप्त हो जाएंगे। जिला बैंक के कार्यालय क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर जिले में सहकरी क्षेत्र पालन केन्द्र प्रारंभ हुआ है। इसके पश्चात समिति में भी प्रारंभ होना है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कमल सिंह हाड़ा, शाखा प्रबंधक एम.एस. खतेडिया, शाखा पर्यवेक्षक संजय नागर बैंक प्रधान कार्यालय से प्रभारी एच.ए. पांडेय आत्मनिर्भर योजना प्रभारी श्रीमती अमृता काला समिति प्रबंधक श्री गर्वरसिंह कठोटा एवं मेघनगर शाखा क्षेत्र की समिति के प्रबंधक व स्टाफ उपस्थित रहे।

अब किसानों को मिलेगा दो करोड़ रूपये तक का ऋण

भोपाल। कृषि विकास और उत्पायदन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य् से कृषक एफ.पी.ओ., स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से बिना किसी जमानत के दो करोड़ रूपये तक ऋण मुहैया कराया जायेगा।

कृषि अधोसंरचना के लिए बिना गारंटी के 7 साल के लिए मिलेगा लोन

मात्र तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की छूट 7 वर्ष की अवधि के लिये किसानों को यह ऋण मिलेगा। कृषक एवं कृषि उद्यमी यह वित्तीतय सहायता भंडार की सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया इकाई (चावल, दाल, आटा चक्की), कस्ट,म हायरिंग सेन्टंर, जैविक इनपूट उत्पाीदन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि कार्यो के लिए आवश्यककता अनुसार कृषि विभाग के माध्यंम से डीपीआर व आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। इच्छुक किसानों, एफ.पी.ओ., स्व्–सहायता समूह, पैक्सा एवं कृषि उद्यमियों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।

किसानों को सहायता राशि के साथ दिया जायेगा 25 प्रतिशत एडवांस फसल बीमा क्लेम

फसल बीमा राशि का भुगतान पिछले दिनों हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है | ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चूका है। राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि एवं बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि दी जाएगी | मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जनवरी तक फसल क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने किसानों को जल्द ही सहायता राशि देने के बात भी कही है | मुख्यमंत्री श्री चौहान राजगढ़ जिले के छायन ग्राम में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सरसों, गेहूँ, चना और मसूर की फसलों का जायजा लेने पहुँचे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई परेशान न हो, संकट के समय सरकार उनके साथ है और उन्हें इस संकट से भी निकालेगी। प्रभावित कृषकों की बेटियों का विवाह है, तो वह भी राज्य सरकार कराएगी। प्रभावित किसानों के कर्ज को अल्पकालीन से मध्यमकालीन करने और एक वर्ष के ब्याज की राशि राज्य शासन द्वारा भरे जाने की घोषणा भी की।

बीमा कम्पनी देगी 25 प्रतिशत अग्रिम क्लेम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। फसलों में 50 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बीमा कम्पनी से 25 प्रतिशत क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष 75 प्रतिशत राशि क्लेम फाइनल होने पर दी जाएगी। राहत राशि राज्य सरकार देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर किसानों को उनकी फसल क्षति की भरपाई की जाएगी। सर्वे सूचि ग्राम पंचायत में होंगी चस्पा मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि फसलों के सर्वे कार्य में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाए और सर्वे सूची ग्राम पंचायत भवन में चस्पा करें। कोई भी किसान सर्वे से छूटना नहीं चाहिये। जिन किसानों को आपत्ति हो उनकी फसल का पुनः सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्वे कार्य चोरी-छुपे नहीं हो, कोई भी प्रभावित कृषक छूटे नहीं। सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की सर्वे का कार्य पारदर्शिता और संवदेनशीलता के साथ हो।

पशुओं की मुत्यु पर भी दी जाएगी सहायता राशि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मसूर की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहाँ प्रति हेक्टेयर 30 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी। पशुओं की मुत्यु होने पर गाय-भैंस के मामले में 30 हजार रूपये प्रति पशु, बैल-भैंसा की मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये, बछड़ा-बछड़ी की मृत्यु होने पर 16 हजार रूपये, बकरा-बकरी की मृत्यु होने पर 3 हजार रूपये तथा मुर्गा-मुर्गी की मृत्यु होने पर 60 रूपये प्रति मुर्गा-मुर्गी राहत राशि प्रदान की जायेगी।

किसानों के सहयोग से "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" का करेंगे निर्माण

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने खण्डवा के रीछी उद्यान प्रक्षेत्र का भ्रमण किया

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि किसानों के सहयोग से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यानिकी किसानों को उन्नत तरीके से जैविक कृषि के लिए उद्यानिकी विभाग लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। विभागीय नर्सरियों में जैविक कृषि कर किसान भाईयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह गुरुवार को खण्डवा जिले के रीछी उद्यान प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बात कही।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने खंडवा में रीछी उद्यान प्रक्षेत्र में जैविक तरीकों से उत्पादित की जा रही फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों से कहा कि सभी किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती करने के लिये प्रेरित करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने प्रक्षेत्र में जैविक खाद के निर्माण की प्रक्रियाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि ड्रिप एरिगेसन से पानी की बचत होती है एवं मल्चिंग विधि से फसलों को खरपतवार से दूर रखा जा सकता है।

सीधे किसानों के खाते में अंतरित करें अनुदान राशि

जैविक उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों के बनायें ग्रुप
हाईटेक फ्लोरीकल्चर गार्डन की डीपीआर बनवायें
उद्यानिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कुशवाह ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाये। किसान निर्धारित स्पेशिफिकेशन की सामग्री को वेण्डर से खरीदने के लिये स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह मंगलवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। एसीएस उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, उद्यानिकी आयुक्त श्री ई. रमेश कुमार और एमडी एम.पी. एग्रो श्री राजीव कुमार जैन बैठक में मौजूद थे। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस योजना में 98 हजार वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली-हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर में फूलों की हाईटेक नर्सरी (फ्लोरीकल्चर गार्डन) की स्थापना के लिये इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ फर्म का चयन कर उससे डीपीआर बनवाई जाये। उन्होंने कहा कि फ्लोरीकल्चर गार्डन अपने प्रकार का प्रदेश का पहला हाईटेक नर्सरी गार्डन होगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि पीएमएफएमई योजना फार्म लाइजेशन आरके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते सुधार हुआ है। बैंकों द्वारा प्रकरणों में स्वीकृतियाँ भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल प्रस्तुत 1327 आवेदनों में से बैंक द्वारा 175 में स्वीकृति दी गई है और 522 प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने विभागीय अधिकारियों को बैंकों से समन्वय कर सभी प्रकरणों में स्वीकृतियाँ दिलाने की बात कही। उन्होंने योजना में जिलेवार प्रगति की समीक्षा भी की।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि जैविक उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों की जिलेवार सूची बनाकर किसानों के समूह बनायें। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये एक जिले में कम से कम एक फसल प्रोडक्ट ऐसा तैयार करें, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में निर्यात किया जा सके। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

आँखों में आंसू न लायें, ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई करेगी सरकार : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के ग्राम खिस्टोन में असमय वर्षा और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना किया। प्रभावित फसलों को देखने मुख्यमंत्री श्री चौहान खेतों में पहुँचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाहर से फसलें हरी दिखती हैं पर खेत में अंदर जाकर देखो तो कुछ नहीं बचा है। प्रदेश में पृथ्वीपुर सहित जहाँ-जहाँ भी फसलों को नुकसान पहुँचा है, उसकी भरपाई की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को शीघ्रता से राहत राशि का भुगतान करायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खेतों में फसल का जायजा लेने के बाद किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि, "घबराना मत, मुसीबत का मिलकर मुकाबला करेंगे। आँख में आंसू मत लाना। सभी संकट से बाहर निकाल लूँगा। जहाँ-जहाँ भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। यदि फसल का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, तो 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जायेगी। फसल बीमा का लाभ अलग से मिलेगा। साथ ही अल्पकालीन ऋण की वसूली स्थगित की जायेगी और अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदला जायेगा।"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनहानि के लिये 4 लाख, गाय-भैंस की मृत्यु पर 30 हजार रूपये और छोटे पशुओं बछड़ा-बछड़ी, बकरा-बकरी तथा मुर्गा-मुर्गी के लिये भी राहत राशि दी जायेगी। यदि मकानों को क्षति हुई है, खपरेल को नुकसान पहुँचा है, तो इसके लिये भी मुआवजा राशि दी जायेगी।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम – 8)

1. प्रकाशन स्थल : मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
2. प्रकाशन अवधि : पाक्षिक
3. मुद्रक का नाम : गणेश प्रसाद मांझी वास्ते–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
4. प्रकाशक का नाम : गणेश प्रसाद मांझी वास्ते–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
5. सम्पादक का नाम : गणेश प्रसाद मांझी वास्ते–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित ई–8/77 शाहपुरा, भोपाल
6. क्या भारतीय नागरिक हैं : हाँ
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो। : यह समाचार पत्र मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं गणेश प्रसाद मांझी एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

सही/–

दिनांक 1 फरवरी 2022

(गणेश प्रसाद मांझी)

प्रकाशक

(पृष्ठ 1 का शेष)

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास.....

सकल घरेलू उत्पाद का रिकॉर्ड बनेगा

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि इस वर्ष राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, जो राज्य के इतिहास में नया अध्याय होगा। केंद्र सरकार ने बालाघाट जिले को मत्स्य-पालन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना में इस वर्ष 20 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

8 हजार 412 ग्राम बारहमासी सम्पर्क से जुड़े

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये की और अटल प्रगति-पथ की स्वीकृति दे दी है। भवनों के निर्माण में गति लाने के लिये मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार 707 किलोमीटर लंबाई की सड़कों, 133 पुलों का निर्माण और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 8 हजार 412 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता से जोड़ा जा चुका है।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राज्य देश में प्रथम

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि राज्य, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 83 लाख 45 हजार किसानों को 5 हजार 191 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में जोड़ा गया

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में जोड़ते हुए वर्ष 2021 में 415 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक और 191 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं में इस वर्ष एक लाख 31 हजार से ज्यादा श्रमिकों को एक हजार 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के हितलाभ मिले हैं।

बहुउद्देशीय वन-धन विकास केन्द्र क्लस्टर

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में बहुउद्देशीय 107 वन-धन विकास केन्द्र क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना का शुभारंभ किया गया है। पेसा कानून का चरणबद्ध क्रियान्वयन और जनसंख्या के मान से बजट में प्रावधान किया गया है।

विमुक्त जाति दिवस मनेगा 31 अगस्त को

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 8 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब बनाए गए हैं और इस वर्ष 6 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय किया गया है।

सिकल सेल रोग उन्मूलन सरकार का संकल्प

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग को रोकना सरकार का संकल्प है। प्रथम चरण में जनजातीय बहुल जिलों- झाबुआ और अलीराजपुर में रोग की जाँच और इलाज का काम पूरी ताकत से शुरू किया गया है। द्वितीय चरण में जनजातीय बहुल इलाकों में सिकल सेल एनीमिया की नि:शुल्क जाँच और इलाज किया जायेगा।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू किये गये हैं। सुदूर क्षेत्रों में 11 नये शासकीय महाविद्यालय, 475 नये दूरस्थ शिक्षा केन्द्र और 6 महाविद्यालयों में नये संकाय प्रारंभ किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में देवारण्य योजना लागू होगी

राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संरक्षण, संग्रहण, उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन के द्वारा किसानों के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से "देवारण्य योजना" लागू की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है। "वैद्य आपके द्वार योजना" में नि:शुल्क आयुष चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश के मॉड्यूल को बेस्ट प्रेक्टिस

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश के ऑनलाइन डायवर्सन मॉड्यूल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की बेस्ट प्रेक्टिस माना गया है। स्वामित्व योजना में आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को ऑनलाइन तैयार करने में प्रदेश, देश में अग्रणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की गई है। जल-जीवन मिशन में 17 हजार 318 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल तथा 16 हजार 853 ग्रामों की 75 समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुख्यमंत्री श्री चौहान का गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम संदेश....

आजादी में क्रांतिकारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमर शहीद क्रांतिकारियों की सही गाथा देश के सामने रखी

मध्यप्रदेश की धरती पर बनाये जा रहे है क्रांतिकारियों के स्मारक

अलग-अलग कलस्टर बनाकर औद्योगिकीकरण की करेंगे नई शुरुआत

इंदौर की जनता ने भी जन-भागीदारी का अद्भुत इतिहास रचा

किसानों के खेत की प्यास बुझाने मध्यप्रदेश ने स्थापित किया नया रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश ने कोरोना से निपटने का जन-भागीदारी मॉडल बनाया

अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में जन-सहयोग का आव्हान

देश को बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी, नेहरु जी, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं बापू जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता, बापूजी तो विश्वबंधु है। आजादी की क्रांतिकारी धारा को भुला दिया गया, एक नहीं अनेक अमर शहीद क्रांतिकारियों की स्मृति को संजो के नहीं रखा गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अमर शहीद क्रांतिकारियों की सही गाथा न केवल देश के सामने रखी बल्कि उनकी स्मृति बनी रहे और प्रेरणा मिलती रहें, इसके लिये देश में अनेक स्मारकों का निर्माण करवाया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। मध्यप्रदेश की धरती पर भी हमने महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टंट्या भील, रघुनाथ शाह-शंकर शाह, भीमा नायक, राणा बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, राजा विभूत सिंह और बादल भोई आदि क्रांतिकारियों के स्मारक बनाकर जो कर्ज राष्ट्र पर उनका है उसे चुकाने का विनम्र प्रयास किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह पंक्तियाँ भी कही - "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर और संविधान बनाने वाली सभी प्रारूप समितियों को नमन करता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर की 125 वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह हमारे संविधान निर्माताओं के चरणों में विनम्र आदरांजली है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान तो निर्जीव है, उसे लोग जीवित बनाते हैं। हम भारत के लोग सचमुच में भारत के संविधान की प्राणवायु और प्राणशक्ति हैं। सही अर्थों में गणतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं - जनता की शक्ति ही, राष्ट्र शक्ति है। उनका मानना है कि कोई भी काम बिना जनता के सहयोग से बिना जनता की भागीदारी से पूरा नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज जब वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है, मुझे प्रसन्नता है मध्यप्रदेश ने कोरोना से निपटने का जन-भागीदारी मॉडल बनाया है। मैं अपने प्रिय बहन-भाइयों और बेटे-बेटियों से कहना चाहता हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का मुकाबला डटकर किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबला करने के लिये हमने जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ बनाई। हमारे जन-प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, समाजसेवियों, धर्मगुरुओं, विभिन्न संस्थाओं ने मध्यप्रदेश को सुरक्षा कवच देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं अहिल्या माँ की पवित्र नगरी में खड़े होकर गर्व से कहता हूँ कि इंदौर की जनता ने भी जन-भागीदारी का अद्भुत इतिहास रचा है। इंदौर और प्रदेशवासियों ने मिलकर कोविड-19 की दूसरी लहर का भी मुकाबला किया है। अभी हम तीसरी लहर के प्रकोप से गुजर रहे हैं। कोरोना रोगियों की संख्या स्थिर होना शुरू हो गई है। सावधानी में ही सुरक्षा है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लगाकर रखे, दूरियाँ बनाकर रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाई। हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को प्रणाम, जिन्होंने भारत में समय रहते एक नहीं दो-दो स्वदेशी वैक्सीन बना ली। मुझे कहते हुए गर्व है कि देश में लगभग 168 करोड़ वैक्सीन डोज़ लगा दिए गए हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर टीका लगाने तक का एक अद्भुत कार्यक्रम जन- सहयोग से संपन्न हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी का इस जीवन रक्षक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्म-निर्भर भारत का मंत्र दिया। आत्म-निर्भर भारत के लिए हमने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प लिया है। अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के लिये हम एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि, कभी मध्यप्रदेश "सड़कों में गड्ढे का प्रदेश" कहा जाता था। आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। अब हमारा संकल्प अटल एक्सप्रेस-वे, नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने का है। यह केवल रोड नहीं, मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होंगे। नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के अलग-अलग कलस्टर बनाकर हम औद्योगिकीकरण की नई शुरुआत करेंगे। भोपाल, इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रियल हब पर हम तेजी से काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पहले प्रदेश में बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। पूर्व में 5 हजार मेगा वॉट की उपलब्धता थी, जो आज बढ़कर 21 हजार मेगावाट से ज्यादा हो गई है। जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसके लिए एक नहीं अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं, सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्यप्रदेश आगे है। एक नहीं

(शेष पृष्ठ 7 पर)

(पृष्ठ 6 का शेष)
अनेक सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन कर तैयार है और ओंकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाकर हम सूरज से बिजली बनाएंगे। यह ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा है, जो पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। हम सूरज से, हवा से, पानी से और बायोमॉस से बिजली बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। नदियों के पानी को रोककर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझाने में मध्यप्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कभी जब यह मांग की गई थी कि नर्मदा का पानी क्षिप्रा में लाओ तो कह दिया गया था कि इंपॉसिबल है, यह हो नहीं सकता। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्द-कोष में नहीं है। नर्मदा जी को क्षिप्रा से जोड़ा गया, गंभीर से जोड़ा गया, अब कालीसिंध और पार्वती नदी से जोड़ रहे हैं। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी से अन्य नदियों में पानी लेकर किसानों के खेतों की प्यास बुझा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल मालवा और निमाड़ में, बल्कि विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी किसान भाइयों के खेतों में पानी पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा साढ़े 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर हमने 43 लाख हेक्टेयर कर दिया और आने वाले समय में इसे 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाएंगे। मध्यप्रदेश के हिस्से की नर्मदा जी की एक-एक बूंद का उपयोग करेंगे। इसके लिये नई-नई सिंचाई योजनाएँ बना-बनाकर न केवल सिंचाई के लिए बल्कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों के साथ गाँव में भी पेयजल संकट को खत्म करने का संकल्प हमने लिया है। प्रदेश के हर एक गाँव में घर-घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन में तेजी से कार्य किया जा रहा है। पिछले डेढ़ साल में 44 लाख घरों में पानी पहुँचाया जा चुका है। शीघ्र ही 2 करोड़ घरों तक पानी ले जाएंगे, जिससे हमारी बहनों और बेटियों को घर से बाहर निकल कर पानी न लाना पड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के मेहनती किसानों ने अन्न के भंडार भरे हैं और उचित दाम देने के लिए हमने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी भी की है। गेहूँ के उत्पादन में मध्य प्रदेश के किसानों ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हमने खरीदी की थी। इस साल 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूँ की धान हमने खरीदी है। अन्न के भंडार भरपूर हैं, रखने की जगह नहीं है, अस्थाई कैंप में रखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न खरीदेंगे नहीं। किसानों की सभी फसलें खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय में फसलों का विविधीकरण जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारी धरती की उर्वरक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए हमें गेहूँ और धान के अलावा बाकी फसलें भी लगानी होगी और साथ में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। जैविक खेती में आज भी मध्यप्रदेश देश में नंबर वन है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले 22 महीने में लगभग 1 लाख 48 हज़ार करोड़ रूपये किसानों के खाते में डाले गये हैं। पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा भी जल्द किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होंगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब "जनता का राज" है। भगवान ने जो संसाधन दिए हैं, वह सब के लिये हैं। लेकिन समाज में असमानता दिखाई देती है। हमारा संकल्प है कि गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम सबके लिए सुलभ कराएंगे। हमारी सरकार गरीब भाई-बहनों को सस्ता राशन देने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और कोविड-19 के कठिन काल में नि:शुल्क राशन देने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 1 साल में 16 हज़ार करोड़ रूपये हमने गरीबों को राशन देने पर खर्च किये है। प्रत्येक माह की 7 तारीख का दिन अन्न उत्सव का दिन होता है, जिसमें गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब का अधिकार उसका मकान है। हमने 28 लाख मकान अब तक बनाए हैं1 ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक मकान बन रहे हैं। हमारी कोशिश है कोई गरीब झोपड़ी में न रहे और जल्दी उनको पक्का मकान बनाकर दिया जाए। इसके लिए गाँव और शहरों में अभियान चलाएंगे। प्रदेश के हर भूमिहीन परिवार को मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना से जमीन का मालिक बनाया जाएगा। शहरों में बहुमंजिल भवन (मल्टी) बनाकर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कि इलाज और उसकी नि:शुल्क व्यवस्था एक बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत अभियान चलाया है। मध्यप्रदेश में योजना में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने आव्हान किया कि जिन पात्र लोगों के कार्ड नहीं बने है, वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। प्रशासन इस काम में शिद्दत से कार्य करे। आयुष्मान कार्ड से सरकारी और शासन से संबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज नि:शुल्क किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सभी जिलों में रोजगार दिवस मनाया। हम तय किया था कि 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने में ही हमने 5 लाख 26 हज़ार लोगों को स्व-रोजगार के लिए अलग-अलग योजनाओं से ऋण दिलवाकर उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाये हैं। यह क्रम जारी रहेगा। आगामी 25 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज की ऋण राशि उपलब्ध करवाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आदर्श व्यवस्था बनाने के लिये हाकर्स कॉर्नर बनाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले साल से अब तक लगभग 44 हजार सरकारी नौकरियों में हमने भर्ती की है। भर्ती का अभियान जारी रहेगा। अगले साल तक एक लाख नौकरियाँ और दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरियाँ रोजगार की पूर्ति नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे बच्चे भी गजब प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्ट-अप के क्षेत्र में इंदौर के नौजवानों ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं। हम जल्द ही स्टार्ट-अप की नई नीति लाने वाले हैं। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि यदि उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसे सरकार के साथ शेयर करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इंदौर देश की स्टार्ट-अप राजधानी बनें। आज मैं कुछ बच्चों से बात भी कर रहा हूँ, जिन्होंने स्टार्ट-अप के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। स्व-सहायता समूह की बहनों ने अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। लगभग 40 लाख बहनें अभियान से जुड़ी है। उनके द्वारा अलग-अलग उत्पाद का निर्माण कर रोजगार के नए-नए अवसर पैदा किये जा रहे हैं। समूह के कामों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। इस साल लगभग 38 हजार करोड़ रूपये का निवेश आया है। प्रदेश के कई क्षेत्र औद्योगिक हब के रूप में उभर रहे है। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई के माध्यम से अलग-अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। हम एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जिससे समाज के हर वर्ग का कल्याण हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए हमने तय किया था कि पेसा एक्ट कानून लागू करेंगे, उस पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। चिन्हित ब्लॉकों में "राशन आपके ग्राम योजना" प्रारंभ कर दी गई है। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक अनुसूचित जाति के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य वर्गों के हित में भी राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश में आज लाड़ली लक्ष्मी योजना में 41 लाख बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी है। वर्ष 2012-13 में जहाँ प्रदेश का लिंगानुपात एक हजार बेटों पर 914 बेटियों का था, वह बढ़कर अब 956 हो गया है। मेरा यह अभियान तब-तक जारी रहेगा, जब तक बेटे और बेटियाँ बराबर की संख्या में जन्म न लें। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए बेटियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएँ बनाई गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोलने का अद्भुत कार्य किया जा रहा है। यह स्कूल 18 से 26 करोड रुपए तक के बनेंगे, जो सर्वसुविधायुक्तहोंगे। मैं जानता हूँ कि हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कई बच्चे विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले प्रतिभावान होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में प्रतिभा का प्रकटीकरण नहीं कर पाते। हमने यह तय किया है कि मध्यप्रदेश में अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी न जानने वाले बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय को भारत के 100 के प्रमुख विश्वविद्यालय में शामिल किये जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी एवं ग्रामीण विकास के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश बनाने में सुशासन हमारा मूल मंत्र है। सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, समाधान ऑनलाइन के साथ मोबाइल पर जन सुविधाएँ देने का नया अभियान हमने चलाया है। जनता को बिना किसी परेशानी के निश्चित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ मिले, इस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह भी फैसला किया है कि असामाजिक तत्वों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हजारों हेक्टर जमीनें हमने माफियाओं से मुक्त कराई है और कई जगह जहाँ इन्होंने कब्जा किया था, अब वहाँ गरीबों के मकान बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।इंदौर में और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान लेकर उभरा है। पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के काम भी व्यापक रूप से किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता में इंदौर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आज इंदौर देश के लिये आइकॉन बन गया है। मध्यप्रदेश स्वच्छता में तीसरे नंबर पर आया है। सभी के मिले-जुले प्रयासों से हम मध्यप्रदेश को स्वच्छता में पहले नंबर पर लाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च में फिर स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होगा। इसमें गाँव हो या शहर, सभी जगह स्वच्छता के नये आयाम स्थापित कर हम मध्यप्रदेश को स्वच्छता में भी नंबर वन बनाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैंने प्रदेशवासियों से अपील की थी कि कुपोषण समाप्त करने के लिए एक आँगनवाड़ी गोद लें। मध्यप्रदेश में 97 हजार आँगनवाड़ी में से 48 हजार आँगनवाड़ी गोद ली गई है। गोद लेने का मतलब उस आँगनवाड़ी में शासकीय सुविधाएँ ठीक से मिले, यह प्रयास करना है। आँगनवाड़ियों में बेहतर काम करते हुए हमे अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कहा कि मैं पिछले दिनों भोपाल और ग्वालियर नगर के भ्रमण पर निकला था। जहाँ कुछ लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए देखा। ऐसे वर्ग की भी चिंता करते हुए हमने रैनबसेरा बनवाए हैं। यहाँ उन्हें आश्रय दिया जा रहा है। साथ ही दीनदयाल रसोई योजना का लाभ भी जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आव्हान किया कि पर्यवरण संरक्षण के लिये परिवार के विभिन्न अवसरों पर पौध-रोपण जरूर करें। मुख्यमंत्री ने सभी से लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी उत्पादों को नकारने का भी आव्हान किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। जनता को सस्ती बिजली देने के लिये 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फालतू बिजली जलाई जाये। उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत हो, बिजली का उतना ही उपयोग करें। बिजली बचाना, बिजली बनाने के बराबर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर शहर और हर गाँव वासी अपने गाँव-शहर को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। उन्होंने नशामुक्ति के लिये भी प्रदेशवासियों का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में सभी अपना योगदान दें।

73 वाँ गणतंत्र दिवस राज्य सहकारी संघ भोपाल में पूरे उत्साह, उमंग, हर्षोंल्लास एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया

भोपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ कार्यालय में ध्वजारोहण किया। श्री ऋतुराज रंजन ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम एवं भाईचारे की भावना के साथ एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। संघ के कल्याण और समग्र विकास के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने सभी से कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी टीकाकरण अवश्य कराएं एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करें।

गणतंत्र दिवस का यह पर्व कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ सहित अन्य सभी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैंक टी.टी. नगर मुख्यालय भोपाल में हर्षोंल्लास से मनाया "73वां गणतंत्र दिवस"

भोपाल। अपेक्स बैंक भोपाल के टी.टी. नगर स्थित मुख्यालय भवन के प्रांगण में एवं छठवीं मंजिल की छत पर 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण श्री नरेश पाल कुमार, प्रशासक, अपेक्स बैंक एवं सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश एवं श्री पी.एस.तिवारी, प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक ने किया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्रीमती अरुणा दुबे, श्री के.के. द्विवेदी, सहायक महाप्रबंधक डॉ. रवि ठक्कर, श्री आर.एस. चंदेल, श्री के.टी.सज्जन, विकअ श्री अरविंद बौद्ध, प्रबंधक श्रीमती ज्योति उपाध्याय, श्री विनोद श्रीवास्तव, उप प्रबंधकगण सर्वश्री विवेक मलिक, समीर सक्सेना, करुण यादव, आर.व्ही.एम.पिल्लई, अरविंद वर्मा, अजय देवड़ा, जी.के. अग्रवाल के साथ अपेक्स बैंक के अनेक अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित हुए ।

ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने "भारत माता की जय" एवं "गणतंत्र-दिवस अमर रहे" के नारे लगाए एवं मिठाई ग्रहण कर आपस में सभी को शुभकामनायें दीं।

केन्द्र इन्दौर द्वारा सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

इन्दौर। अपर मुख्य सचिव सहकारिता द्वारा म. प्र. राज्य सहकारी संघ की वार्षिक साधारण सभा में राज्य सहकारी संघ को प्रशिक्षण निधि का भुगतान करने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए कार्ययोजना बनाकर सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये। इन निर्देशो के पालन में म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल के प्रबंध संचालक श्रीमान ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में कार्ययोजना बनाकर प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन प्रदेश स्तर पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं में किया जा रहा है। इस कार्ययोजना अनुसार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा माह जनवरी 22 की दिनांक 06.01.22 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., देवास मुख्यालय, 15.01.22 को आनेन्दश्वरी नागरिक सहकारी बैंक लि., उज्जैन, 19.01.22 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., धार मुख्यालय, दिनांक 24.01.22 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., धार शाखा मनावर व दिनांक 25.01.22 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि., धार शाखा राजगढ़ में "साइबर सिक्युरिटी एवं बैकिंग क्षैत्र में ऑनलाईन फ्रॉड" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्था स्थल पर किया गया। जिसमें बैंको के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने कार्य समय के पश्चात शाम 5 से 7 बजे तक उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रशिक्षण में सायबर अपराध के तरीके व बैंको द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा उपाय व आई. टी. एक्ट 2000 के बारे में जागरूक किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने वर्तमान परिस्थिति अनुसार यह कार्यक्रम उनके कार्यक्षेत्र के लिये अति उपयोगी बताया। संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

एचडीसीएम प्रशिक्षणार्थियों का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

इन्दौर – म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाईन हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मेनेजमेंट (एच.डी.सी.एम.) सत्र क्रमांक 1 के इन्दौर संभाग के प्रशिक्षणार्थियों का व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट के मार्गदर्शन में इन्दौर जिले की देवी अहिल्या विपणन सहकारी संस्था, जिला सहकारी संघ, सहकारी शीत गृह राऊ, पेक्स निरंजनपुर आदि सहकारी संस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली, प्रबंधकीय व्यवस्था, व्यवसायिक गतिविधियॉ, संस्था की भविष्य की योजनायें, आर्थिक स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया गया। जिससे प्रशिक्षणार्थियों का सहकारिता संबंधी ज्ञानवर्धन हुआ। संस्थाओं द्वारा दिये गये सहयोग के लिये केन्द्र के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट व प्रशिक्षार्थियों द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

शीघ्र आयें प्रवेश पायें

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-

संपर्क :-

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।